Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405160

नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति और भारत-नेपाल सम्बन्ध

परमेश्वरी[1]

शोध सार: नेपाल दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य है, जिसकी विदेश नीति परंपरागत रूप से भारत-केंद्रित रही है। किंतु हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक एवं सामरिक उपस्थिति ने इस पारंपरिक समीकरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से 2015 के बाद चीन–नेपाल संबंधों में तीव्रता आई है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत–नेपाल संबंधों पर पड़ा है। यह शोध-पत्र नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति के विभिन्न आयामों—जैसे बेल्ट एंड रोड पहल (BRI), अवसंरचनात्मक निवेश, सुरक्षा सहयोग, राजनीतिक संपर्क तथा सॉफ्ट पावर—का विश्लेषण करता है और यह जांचने का प्रयास करता है कि ये कारक भारत–नेपाल संबंधों की प्रकृति, दिशा और संतुलन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। शोध पत्र यह भी स्पष्ट करता है कि नेपाल किस प्रकार भारत और चीन के बीच संतुलनकारी विदेश नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है। शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है कि नेपाल में चीन की बढ़ती भूमिका ने भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती दी है, किंतु भारत–नेपाल संबंधों की रणनीतिक, सांस्कृतिक और जन-स्तरीय गहराई को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यह अध्ययन भारत के लिए नीतिगत चुनौतियों एवं संभावनाओं को रेखांकित करता है तथा सुझाव देता है कि आपसी विश्वास, विकास साझेदारी और संवेदनशील कूटनीति के माध्यम से भारत–नेपाल संबंधों को पुनः सुदृढ़ किया जा सकता है।

बीज शब्द : दक्षिण एशिया, भू-राजनीति, शक्ति सन्तुलन, आर्थिक सहयोग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पड़ोसी नीति

प्रस्तावना

नेपाल हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बसा है। भारत उसका निकटतम पडोसी राष्ट्र है। इनकी भौगोलिक सीमायें एक दूसरे से मिली हुई है। जब से तिब्बत चीन के प्रत्यक्ष शासन में आया है, तब से नेपाल की स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी है। चीन और भारत के बीच नेपाल एक मध्यवर्ती राज्य बन गया है। इस कारण चीन और भारत के सम्बन्धों में नेपाल एक अत्यन्त प्रभावकारी तत्व बन गया है। निकटतम पड़ोसी होने के कारण नेपाल का भारत के लिए सामरिक महत्व रखना बिल्कुल स्वाभाविक है। भारत के स्वतंत्र होने के समय जो नयी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियाँ उत्पन्न हुईं उसने नेपाल की स्थिति को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया।

[1] *पीएच.डी. शोधार्थी, दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर*

Lyceum India Journal of Social Sciences || ISSN (Online): 3048-6513
Volume: 3 Issue: 1 || January 2026 || DOI: 10.5281/zenodo.18405160

चीन की विदेश नीति में नेपाल का रणनीतिक महत्व

नेपाल भौगोलिक रूप से हिमालयी देश है। नेपाल की सुरक्षा में अहम भूमिका विशालकाय हिमालय निभाता है। भारत तथा चीन दो महान शक्तियों के बीच स्थिति होने के कारण इसका महत्व एक निर्णायक संतुलन को स्थापित करने के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस कारण चीन के लिए नेपाल को कुछ भी करके अपनी ओर आकर्षित करना अति महत्वपूर्ण हो गया है। भारत और चीन के मध्य वर्ष 1962 में किया गया युद्ध तथा अरुणाचल प्रदेश के नेफा में आक्रमण के कारण नेपाल अपनी भू-सामरिक महत्व को सही से समझने लगा कि यह चीन व भारत के लिए एक मध्य का देश होने के कारण मजबूत स्थिति में है। चीन भी इस विषय से भली-भांति परिचित था जिस कारण नेपाल के महत्व को समझते हुए चीन अपने सामरिक संबंधों को नेपाल के साथ बनाने के लिए अति सक्रिय हुआ।

चीन के तानाशाह माओ-जे डोंग ने पांच ऊंगलियों का सिद्धांत दिया था जिसके तहत तिब्बत को चीन के दाहिने हाथ की हथेली माना तथा लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरूणाचल प्रदेश को चीन की पांच ऊंगलियां माना। चीन में जब गृह युद्ध वर्ष 1940 में चल रहा था, तब माओत्से तुंग द्वारा नेपाल को चीन का क्षेत्र घोषित करने संबंधित सार्वजनिक बयान दिए थे। वर्ष 1954 में चीन के अधिकारी द्वारा तिब्बत में अपने मीडिया साक्षात्कार में यह दावा किया जा रहा था कि चीन, सिक्किम, नेपाल, भूटान और नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर) को 'गलत कब्जे से मुक्त कराकर चीन के अंग के रूप में वर्तमान समय में भी शामिल कर लेगा, परंतु चीन द्वारा नेपाल के लिए परिकल्पित इस नीति का अस्तित्व औपचारिक तौर पर वर्तमान समय में चीन के अधिकारियों द्वारा भी पुष्टि नहीं किया जाता है, परंतु चीनी मंशा नेपाल को अपना भू-भाग समझना और अवसर पाते ही चीन में उसे शामिल करने के प्रयास भविष्य में भी देखे जाने की संभावना है।

सन् 1955 में नेपाल और चीन के बीच साझेदारी संबंध स्थापित किये गए। इसके बाद नेपाल के द्वारा तिब्बत को चीन के क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। सन् 1960 में चीन और नेपाल के मध्य शांति व मैत्री संधि को संपादित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ एवं नेपाल के लिए यह दुविधापूर्ण स्थिति थी कि वह दो महाशक्तियों के बीच अवस्थित है। अतः किसे समर्थन प्रदान किया जाए एवं किसे नहीं जिससे भारत-चीन के युद्ध में नेपाल को प्रभावित न होना पड़े। इस कारण नेपाल द्वारा कूटनीतिक कदम उठाया गया एवं दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लिया गया। इसका प्रभाव भारत-नेपाल रिश्तों पर भी पड़ा, क्योंकि भारत संकट की इस घड़ी में नेपाल से समर्थन की उम्मीद कर रहा था। नेपाल के महिपाल वीरेंद्र द्वारा भारत और चीन के मध्य स्थित एक शांति के क्षेत्र के रूप में घोषित करने की मांग वर्ष 1970 में की गई। इस आलोक में भारत ने अपना विचार दिया कि संपूर्ण दक्षिण एशिया को शांति का क्षेत्र घोषित होना चाहिए, सिर्फ एक देश को इसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक सभी दक्षिण एशियाई देश इस पर सहमति नहीं देते, तब तक सिर्फ नेपाल को 'शांति के क्षेत्र के रूप में घोषित करने के विषय पर स्वीकृति प्रदान करने का कोई औचित्य

नहीं है। अतः भारत द्वारा नेपाल की इस मांग के प्रति रूचि नहीं ली गई, परंतु चीन द्वारा कूटनीतिक कदम उठाते हुए नेपाल की इस मांग को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। चीन नेपाल को अपने निकट लाने तथा भारत से नेपाल को दूर रखने के किसी भी अवसर को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि तिब्बत पर कब्जे के बाद अब चीन की सीमा स्पष्ट रूप से नेपाल के साथ लगती है। नेपाल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध को निर्मित करना चीन के लिए सामरिक रणनीतिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन नेपाल को भारत के खिलाफ करके नेपाल का इस्तेमाल भारत के विरूद्ध दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कमजोर कर शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। चीन दक्षिण एशिया के हिमाचल प्रदेश के सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों को निर्मित करने संबंधित विदेश नीति को महत्ता दे रहा है जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण चीन भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में तथा भारत के पड़ोसी देशों के साथ बहुत चुनौतीपूर्ण एवं कमजोर करना चाहता है। चीन की मंशा विश्व व्यवस्था में अपना वर्चस्व कायम करने की है। वह अमेरिका तथा अन्य देशों को पीछे छोड़ समस्त विश्व के समक्ष शक्ति के एक नवीन सर्वोच्च केंद्र बिंदु के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है। इस कारण चीन अपने पड़ोसी देश नेपाल को भी अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करता रहता है। इस संदर्भ में चीन द्वारा नेपाल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारी आर्थिक सहायता दी जा रही है। चीन द्वारा नेपाल में कई विकास कार्यों को संपादित किया जा रहा है। चीन अपनी सामरिक सुरक्षा संबंधित हितों के वजह से नेपाल के साथ अपने रिश्तों को अत्यंत घनिष्ठ बनाये रखना चाहता है। चीन का तिब्बत पर अपना अधिकार कर लेने के बाद से तिब्बत से करीबन दो हजार तिब्बती शरणार्थी नेपाल में प्रवास कर रहे हैं जो चीन के लिए वैश्विक रूप से चिंता का कारण बना हुआ है। ये शरणार्थी नेपाल के रास्ते भारत के धर्मशाला में स्थित तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के निवास स्थान तक आते हैं जिसके वजह से चीन इस आवागमन के मार्ग को नेपाल में बाधित करना चाहताहै। इस कारण चीन नेपाल में एक स्थिर व चीन समर्थक सरकार के शासन की चाह रखता है तथा अपने इस मंशा की पूर्ति के लिए नेपाल की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करता है। नेपाल की साम्यवादी विचारधारा की सरकार चीन समर्थक मानी जाती है जो चीन से नेपाल के रिश्तों को प्रगाढ़ तथा भारत से दूरी बनाये रखने का पक्षकार है। इसलिए, चीन तिब्बतियों के धर्मशाला तक पहुंचने के मार्ग को नेपाल की सहायता से बंद करने का दवाब डालता है एवं यह सुनिश्चित करना चाहता है कि चीन और तिब्बत के बीच का सीधा संपर्क चीन की सुरक्षा के लिए खतरा न बन पाए।

चीन अपने संबंध नेपाल के साथ विकसित एवं प्रगाढ़ करके नेपाल की भारत से सटे सीमाओं का प्रयोग भारत के विरोध में करके भारत पर अपनी दृष्टि बनाये रखना चाहता है। चीन नेपाल को भारत के विरूद्ध एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके लिए नेपाल को विकास के नाम पर आर्थिक सहायता व अन्य प्रकार के कई लुभावने परियोजनाओं के द्वारा प्रभावित करना चाहता है जिससे भविष्य में नेपाल पर कर्ज का बोझ डालकर व चीन अपनी प्रचलित नीति 'डेथ ट्रैप' में फंसा कर नेपाल पर अपना पूर्ण नियंत्रण रख सके और नेपाल के सारे तंत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की चाहत की पूर्ति हो सके।

नेपाल की महत्वकांक्षा: चीन एक अवसर के रूप में

नेपाल-चीन भी अब तिब्बत के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। चीन एक विस्तारवादी तथा आक्रामक राष्ट्र होने का परिचय समय-समय पर देता आया है। भारत के साथ चीन का संघर्ष व मनमुटाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में चीन द्वारा अपनी कूटनीतिक चालों को वास्तविक रूप देने के लिए नेपाल का साथ चाहिए होगा एवं नेपाल वर्तमान समय में सिर्फ भारत पर सामरिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहता। नेपाल की महत्त्वकांक्षाएं आज के समय में पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हुई है। नेपाल अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अब अपने अन्य शक्तिशाली पड़ोसी मित्र विशेषकर चीन की तरफ भी देखने लगा है एवं चीन सहायता के नाम पर नेपाल पर नियंत्रण करने की मंशा में सहायता करने हेतु बैठा इंतजार ही करते आ रहा था। दो शक्तिशाली व संघर्षशील राष्ट्रों के मध्य का देश होने के कारण नेपाल अपनी महत्ता को चीन और भारत के संदर्भ में भली-भांति समझता है। इस प्रकार नेपाल अपनी स्थितियों में सुधार व विकास के लिए चीन का भी सहायता लेना चाहता है, ताकि नेपाल की मदद के लिए भारत तथा चीन की मध्य होड़ लग जाए व परिणामस्वरूप नेपाल को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चीन के नजदीक जा कर नेपाल यह चाहता है कि इसके द्वारा वह भारत को प्रतिसंतुलित कर सके। छोटे देश नेपाल को सदैव यह भय रहता है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सुरक्षात्मक एकात्मकता के कारण भारत द्वारा नेपाल को भविष्य में सिक्किम की तरह भारतीय संघ का एक राज्य न बना लिया जाए, इसलिए नेपाल भारत के दुश्मन चीन को भी अपने निकट लाने का प्रयास करता रहता है। हालांकि, नेपाल का भारत के प्रति इस भय का कोई आधार नहीं है, न ही भारत नेपाल ने इस परिप्रेक्ष्य में कोई बयान दिया है। भारत नेपाल की संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाये रखने का पुरजोर तरीके से पक्षधर हमेशा से रहा है।नेपाल को चीन द्वारा भारी अनुदान राशि मुहैया कराई जाती है। नेपाल ने चीन से वर्ष 2022 में 15 बिलियन की सहायता राशि अपने विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राप्त किया है। इसके साथ ही नेपाल को चीन ने 30 लाखआरएमबी (चीन की आधिकारिक मुद्रा) मूल्य की आपदा राहत सामग्री भी दी। चीन की प्रस्तावित योजना 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल का भागीदार देश नेपाल भी है। इसके पहल में शामिल होने का मुख्य कारण नेपाल का चीन के प्रभाव में होना था। इस परियोजना द्वारा नेपाल में संरचनाओं व कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना है तथा नेपाल इस विषय से संतुष्ट है।

नेपाल की माओवादी पार्टी को चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है तथा साम्यवादी सरकार के निर्माण में चीन नेपाल की आतंरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर माओवादी दल की सरकार बनाने में अहम योगदान देता है। इस कारण विचारात्मक सोच के मिलने तथा सत्तात्मक पद प्राप्ति की लालसा में नेपाल की साम्यवादी दल चीन के प्रति निकट व नरम रवैया रखते हैं एवं चीन के समर्थन को अपनी हितों की पूर्ति के रूप में देखते हैं।

भारत द्वारा जितनी भी विकास परियोजनाएं नेपाल में प्रस्तावित हैं, उन सभी परियोजनाओं को समय सीमा के अंतराल में भारत द्वारा पूरा नहीं किया जा सका है। कई परियोजनाएं लंबे समय तक लंबित रही हैं। इस कारण नेपाल भारत से नाखुश व असंतुष्ट रहता है। इसके विपरीत देखा जाए तो चीन द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं का कार्य समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाता है तथा नेपाल के विकास में यह अहम योगदान देता है। इस वजह से भी नेपाल चीन से अपने रिश्तों को मजबूत व घनिष्ठ बनाये रख कर नेपाल के विकास में भारत को प्रतिस्थापित कर अब चीन को प्रमुखता प्रदान करता है।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्ध और चीन कारक

स्वतंत्र भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में ही नेपाल के साथ समानता को प्रमुख आधार मानकर अपने रिश्ते को विकास की राह पर अग्रसित करने के लिए नेपाल को सभी तरह की सहायता दी है। जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य इत्यादि प्राथमिक तौर से उपलब्ध करायी गई और यह सहायता वर्तमान समय तक भी उपलब्ध होते आ रहे हैं, किंतु मौजूदा समस्त सहायताओं के बावजूद वर्तमान समय में भारत-नेपाल संबंधों के मित्रवत व घनिष्ठ संबंधों के निर्वहन में कुछ ऐसे कारकों एवं मुद्दों की मौजूदगी है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के विकास में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। जैसे चीनी कारक, आतंकवाद, नेपाली माओवादी गतिविधियां, भारत-नेपाल सीमा मुद्दा, तश्करी, शरणार्थी समस्याएं, सुस्ता सीमा मुद्दा, रटहट का जल भराव मुद्दा, काला पानी विवाद और मेची नदी मुद्दा इत्यादि।

इन समस्त मुद्दों में से चीन से प्राप्त भारत-नेपाल संबंधों की चुनौतियां सबसे गंभीर व चिंता का विषय है। चीन सदैव भारत-नेपाल मधुर संबंधों को निरंतर स्थापित करने के मार्ग में बाधक रहा है। चीन भारत-नेपाल के बीच संबंधों का संतुलन बनाये रखने में सदा एक निर्णायक कारक के रूप में चुनौती उत्पन्न करते आ रहा है। नेपाल ने 'चीन कार्ड' का प्रयोग भारत-नेपाल संबंधों को प्रतिसंतुलित करने के लिए करता आ रहा है। अतः चीन द्वारा भारत के संबंध नेपाल के साथ प्रगाढ़ बनाये जाने में बाधाओं का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

नेपाल में चीन का राजनीतिक प्रभाव और भारत की विदेश नीति के लिए उभरती चुनौतियाँ

वर्ष 2006 में नेपाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसके तहत माओवादियों का नेपाल की राजनीति की मुख्य धारा में आना हुआ। इसके बाद नेपाल में राजशाही का अंत हुआ। माओवादियों तथा सात दलों के बीच गठबंधन का समझौता हुआ एवं नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ व इसी के साथ नवीन नेपाल का भी उदय हुआ। वर्ष 2006 के बाद नेपाल लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु एवं गणतांत्रिक राज्य बन गया। एक नए नेपाल के निर्माण के लिए माओवादियों तथा अन्य दलों के बीच समझौता हुआ। जिसके अनुसार माओवादी दल नेपाल की राजनीति में भाग लेंगे व माओवादियों ने प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया।

इसके बाद, वर्ष 2008 में नेपाल के संविधान सभा के चुनाव में माओवादी दल सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया। जबकि, नेपाली कांग्रेस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था एवं तीसरे स्थान पर मार्क्सवादी-लेनिनवादी दल रहा था। इस चुनाव का परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहा था, क्योंकि माओवादियों का शासन भारत-नेपाल रिश्तों की अनुकूलता हेतु बड़ी चुनौती है। माओवादियों का निकट संबंध चीन के साथ रहा है। उदाहरण के लिए, चीन द्वारा माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने हेतु नेपाल के सांसदों को 500 मिलियन रूपये दिये गए थे। इस संदर्भ में प्रचंड और चीन के अधिकारियों के बीच बातचीत का टेप रिकॉर्ड मीडिया द्वारा प्रसारित किया गया था। नेपाल ने सफाई देते हुए इसे विरोधी शक्तियों जैसे- भारत, अमेरिका और नेपाल की सेना की साजिश करार दिया था। इसके साथ ही माओवादी दल भारत को साम्राज्यवादी दल की संज्ञा देते हुए भारत के संबंध नक्सलियों से होने के आरोप लगाते हैं। माओवादी दल अन्य दलों पर आरोप लगाते हैं कि वे भारत के साथ मिले हुए हैं। इस तरह नेपाल में राजशाही तथा लोकतंत्र की बहाली दोनों ही परिस्थितियों में संबंधों को निरंतर सही दिशा में नहीं पाया जा सका एवं हमेशा संकट की स्थिति बनी रही। जिसमें चीन द्वारा नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के बाद भी नेपाली माओवादी दल को अपना पिछलग्गू बनाने की कवायद हमेशा की गई। माओवादी दल भी चीन के प्रभाव व सत्ता प्राप्ति की लालसा में भारत के विरोध में रहते हैं जिससे भारत-नेपाल संबंध अनुकूलता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके।

नेपाल के माओवादियों का संबंध चीन के साथ जग जाहिर है। चीन दक्षिण एशिया में भारत को अपना प्रतिस्पर्धी मानकर भारत को हमेशा घेरने के प्रयास में सक्रिय रहता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चीन नेपाल के माओवादियों की मदद लेकर भारत में नेपाल-भारत की सीमा से कन्याकुमारी तक एक लाल गलियारा बनाने की गुप्त योजना पर कार्य कर रहा है। इसमें वह नेपाल की माओवादी सरकार से मदद लेने का इच्छुक है। इस योजना के द्वारा चीन भारत में अवैध रूप से अपने अस्त्र-शस्त्रों एवं कई अन्य साजो-सामान को पहुंचा सके, जिससे भारत में आतंरिक अशांति को उत्पन्न कर सके।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यदि माओवादी आंदोलन से नेपाल की राजनीति गर्माती है तो यह निश्चित ही भारत की आतंरिक सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। भारत को भी चाहिए कि नेपाल के आतंरिक मुद्दों में हस्तक्षेप न करे, परंतु इस विषय पर भी प्रकाश डालने से बचा नहीं जा सकता है कि यदि नेपाल में अव्यवस्था फैलती है या नेपाल में सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है तो नेपाल से लाखों की संख्या में शरणार्थियों के भारत में आने की संभावनाएं हैं। अतः इस वजह से भारत नेपाल में माओवादियों की गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत को हमेशा सुसज्जित रहना होगा।

निष्कर्ष

नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत-नेपाल संबंधों की पारंपरिक संरचना को नई चुनौतियों और अवसरों दोनों के साथ पुनर्परिभाषित किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, निवेश, और कूटनीतिक सक्रियता के माध्यम से चीन ने नेपाल में अपनी रणनीतिक पहुँच को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित किया है। इसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा आयामों तक भी विस्तृत है, जिससे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता के कारण भारत-नेपाल संबंध विशेष और बहुआयामी रहे हैं। खुली सीमा, सामाजिक-सांस्कृतिक साझेदारी और आर्थिक निर्भरता भारत को नेपाल का स्वाभाविक साझेदार बनाती है। किंतु हाल के वर्षों में कुछ कूटनीतिक असंतुलन, विश्वास की कमी, और आंतरिक राजनीतिक हस्तक्षेप की धारणाओं ने इन संबंधों को प्रभावित किया है, जिसका लाभ चीन ने रणनीतिक रूप से उठाया है।

फिर भी, नेपाल की विदेश नीति मूलतः संतुलन (balancing) पर आधारित रही है, जहाँ वह भारत और चीन दोनों के साथ सहयोग बनाए रखते हुए अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है। इस संदर्भ में भारत के लिए आवश्यक है कि वह नेपाल के साथ अपने संबंधों को केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समानता, आपसी सम्मान और विकास साझेदारी के आधार पर पुनर्स्थापित करे। कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, व्यापार सुगमता, और लोगों-से-लोगों के संपर्क को सुदृढ़ करना भारत की प्रभावशीलता को पुनः मजबूत कर सकता है।

अंततः, नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति को भारत-नेपाल संबंधों के लिए पूर्णतः नकारात्मक चुनौती के रूप में देखने के बजाय, इसे भारत के लिए आत्ममंथन और रणनीतिक पुनर्संयोजन का अवसर माना जाना चाहिए। एक संवेदनशील, दीर्घकालिक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर भारत न केवल नेपाल के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ

एम.के. सिंह, नेपाल फॉरेन पॉलिसी, सुमित इण्टरप्राईजेज, नई दिल्ली, 2011

एस.डी. मुनि, फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपाल,एड्रोइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2016

अर्चना कुमारी, नेपाल राजनीति: संविधान एवं प्रजातंत्र का विकास, एम.पी. पब्लिशर्स, दिल्ली, 2008

निर्मला अग्रवाल, भारत नेपाल सम्बन्ध,ए.बी.डी. पब्लिश्र्स, जयपुर, 2003

शिव बहादुर सिंह, नेपाल शासन एवं राजनीति, गंगा संस एण्ड ग्रैन्ड संस, वाराणसी, 2001

बी.सी. उप्रेति, उद्हाब पी.डी. प्यूक्रेल, कन्टम्परेरी नेपाल, कलिंगा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2012

कृष्णानंद शुक्ल, भारत नेपाल सम्बन्ध, अंकित पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2011

प्रमोद जयसवाल, गीता कोचर, इण्डिया चाईना-नेपाल डिकोडिंग ट्राइलेटरलिज्म, जी.बी. बुक्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016

अनिल कुमार झा, इण्डो नेपाल फॉरेन पॉलिसी, रीड पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2013

अंशु पाण्डेय, भारत-नेपाल सम्बन्ध, नवराज प्रकाशन, दिल्ली, 2004

कृष्णा कुमारी, इण्डिया-नेपाल रिलेशंस देन एंड नाऊ, प्रशान्त पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2019

प्रमोद जयसवाल, अण्डरस्टैंडिंग नेपाल इन कन्टम्परेरी टाईम्स, सिनजि बुक्स इण्डिया, नई दिल्ली, 2017

मुकेश कुमार सिंह, नेपाल इन चाईनाज फॉरेन पॉलिसी, प्रशान्त पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,2014

कलिम बहादुर, महेन्द्र पी. लामा, न्यू परस्पेक्टिव ऑन इण्डिया नेपाल रिलेशंस, हर आनंद, दिल्ली, 1995

प्रकाश सिंह, नेपाल-इण्डिया ओपन बोर्ड प्रॉब्लम्स एण्ड परस्पेक्टिव, सुमित इण्टरप्राइजेज, नई दिल्ली, 2016

वी.एस. बघेल, भारत नेपाल संबंधों में चीन की भूमिका, दिल्ली, बुक क्राफ्ट पब्लिशर्स,2025

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the publisher, editors, or the editorial board.*